

# Daily Current Affairs

Date : 04 May, 2026



## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI) : राज्य में करोला पंचायत अव्वल
2.	'जयपुर मेट्रो फेज - 2' को वित्तीय स्वीकृति
3.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. वाटर होल पद्धति द्वारा प्रदेश में वन्यजीव गणना
4.	ISSF जूनियर विश्व कप, 2026
5.	ऑस्कर श्मिट
6.	15 वाँ यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड, 2026
7.	सुपर एल नीनो
8.	राज्यों की वित्तीय स्थिति
9.	ई-कोर्ट मिशन
10.	USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट
11.	भारत में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण संकट
12.	प्रोजेक्ट 17A पोत

--:1:--



## राजस्थान परिदृश्य



### पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI) : राज्य में करोला पंचायत अव्वल



#### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI) का दूसरा संस्करण जारी किया।



#### मुख्य बिन्दु:

- यह इंडेक्स 9 विषयगत क्षेत्रों में 150 से अधिक संकेतकों पर देश भर की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों का आकलन करता है।
- राजस्थान की कुल 11037 ग्राम पंचायतों को इस इंडेक्स में शामिल किया गया।
- राजस्थान में प्रथम स्थान** : जालौर जिले की करोला पंचायत राजस्थान में पहले पायदान पर रही।
- नोट** : अप्रैल, 2025 में जारी 'पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स' के प्रथम संस्करण में डूंगरपुर जिले की पिंडावल पंचायत राज्य में पहले पायदान पर रही थी।
- इंडेक्स का उद्देश्य** : ग्रामीण भारत में 'सतत् विकास लक्ष्यों - 2030' को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की सुविधा प्रदान करना।

यह रैंकिंग 9 थीम के आधार पर प्रदान की गई है, जिसमें शामिल हैं -

- गरीबी-मुक्त और संवर्धित आजीविका युक्त पंचायत।
- स्वस्थ पंचायत।
- चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत।
- पर्याप्त जल युक्त पंचायत।

# Daily Current Affairs

Date : 04 May, 2026



5. स्वच्छ और हरित पंचायत।
6. आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचे वाली पंचायत।
7. सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत।
8. सुशासन युक्त पंचायत।
10. विमन फ्रेन्डली पंचायत।

## रैंकिंग में राजस्थान की शीर्ष - 5 पंचायतें:

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	जिला	PAI स्कोर
1.	करोला	जालौर	77.89
2.	कान्ति	भीलवाड़ा	76.99
3.	तापू	जोधपुर	76.56
4.	लक्ष्मीपुरा	टोंक	76.41
5.	गेगा का खेड़ा	भीलवाड़ा	75.95

## रैंकिंग में राजस्थान की अंतिम - 5 पंचायतें:

ग्राम पंचायत	जिला	PAI स्कोर
नरसिंहपुरा	पाली	14.07
हरनावा	डीडवाना - कुचामन	28.22
गेराई	करौली	29.82
सोगावास	नागौर	30.01
रणपुर	उदयपुर	30.04

--3--

# Daily Current Affairs

Date : 04 May, 2026



## 9 थीम आधारित रैंकिंग में राजस्थान की प्रमुख पंचायतें:

टी1-पंचायत में गरीबी मुक्त और आजीविका में वृद्धि	टी2-स्वस्थ पंचायत	टी3-बास-अनुकूल पंचायत
सर्वश्रेष्ठ पंचायत	सर्वश्रेष्ठ पंचायत	सर्वश्रेष्ठ पंचायत
93.39	91.33	92.94
भीमपुर	शंख	दादिया रामपुरा
टी4-जल पर्याप्त पंचायत	टी5-स्वच्छ और हरित पंचायत	टी6-आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत
सर्वश्रेष्ठ पंचायत	सर्वश्रेष्ठ पंचायत	सर्वश्रेष्ठ पंचायत
89.07	94.29	88.82
सुवानिया	हिरना	सेमालिया पीलखेत
टी7-सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत	टी8-सुरासन वाली पंचायत	टी9-महिला अनुकूल पंचायत
सर्वश्रेष्ठ पंचायत	सर्वश्रेष्ठ पंचायत	सर्वश्रेष्ठ पंचायत
88.78	90	76.39
इंरलसर	सुरनवाली	भैसाना

### अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

इस रैंकिंग में पंचायतों को 5 श्रेणियों में बाँटा गया है:

- अचीवर (A ग्रेड, 90-100 पॉइंट),
- फ्रंट रनर (A ग्रेड, 75-90 पॉइंट),
- परफॉर्मर (B ग्रेड, 60-75 पॉइंट),
- एस्पिरेंट (C ग्रेड, 40-60 पॉइंट)
- बिगिनर (D ग्रेड, 0-40 पॉइंट)।

--:4::--



## 'जयपुर मेट्रो फेज - 2' को वित्तीय स्वीकृति

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने जयपुर मेट्रो फेज - 2 परियोजना के लिए ₹13,037.66 करोड़ का औपचारिक स्वीकृति आदेश जारी किया।

### मुख्य बिन्दु:

- राजस्थान में यह पहली बार है, जब किसी योजना को वित्तीय स्वीकृति न्यूनतम समय में प्रदान की गई।
- जातव्य है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 8 अप्रैल, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी।
- फेस - 2 की कुल लागत :** ₹13,037.66 करोड़ रुपये। (PIB के अनुसार)
- विस्तार :** प्रह्लादपुरा से टोड़ी मोड़ तक कुल 36 मेट्रो स्टेशन।
- कुल लंबाई :** 41 किलोमीटर द्वारा उत्तर-दक्षिण मेट्रो गलियारा निर्मित किया जाएगा।
- हिस्सेदारी :** भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50:50 प्रतिशत।
- कार्यान्वयन :** राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (RMRCL)
- कार्यावधि :** सितंबर, 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य।
- यह परियोजना राजस्थान सार्वजनिक परिवहन-केंद्रित विकास नीति-2025, प्रस्तावित महानगरीय परिवहन प्राधिकरण सुधार और राष्ट्रीय सतत् शहरी परिवहन उद्देश्यों के अनुरूप है।

# Daily Current Affairs

Date : 04 May, 2026



**फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:**

**जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का चरणबद्ध विस्तार (राजस्थान आर्थिक समीक्षा - 2025-26)**

चरण	विवरण	लागत	वित्त पोषण
चरण-1A (मानसरोवर से चाँदपोल तक)	संचालन - 3 जून, 2015 से।	₹2023 करोड़।	पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित।
चरण-1B (चाँदपोल से बड़ी चौपड़)	संचालन - 23 सितम्बर, 2020 से। लंबाई - 2.01 किलोमीटर। नोट : निर्माण के दौरान शहर की विरासत को संरक्षित रखते हुये कार्य किया गया।	₹1126 करोड़	एशियाई विकास बैंक (ADB) से ₹810 करोड़ का ऋण, शेष राजस्थान सरकार द्वारा।
चरण-1C (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर)	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा DPR तैयार कर दी गई है।	₹1511.07 करोड़	राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRCL) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। (मेट्रो रेल नीति 2017 के 50:50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत)

--:6:--

# Daily Current Affairs

Date : 04 May, 2026



चरण-1D (मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड)	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा DPR तैयार कर दी गई है। परियोजना कार्यान्वयन हेतु कार्य प्रगति पर है।	₹222.15 करोड़	राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRCL) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। (मेट्रो रेल नीति 2017 के 50:50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत)
चरण-2 (प्रह्लादपुरा से टोड़ी मोड़)	जयपुर मेट्रो ने यातायात एवं परिवहन परामर्शदाता के रूप में मैसर्स राइट्स लिमिटेड को नियुक्त किया है। फेज-2 (प्रहलादपुरा /सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र/हल्दीघाटी मार्ग/हवाई अड्डा/अंबाबाड़ी/विद्याधर नगर/टोंक रोड) हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) मैसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई है।	₹13532.92 करोड़	राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRCL) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। (मेट्रो रेल नीति 2017 के 50:50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत)

--7--

## ✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p><b>वाटर होल पद्धति द्वारा प्रदेश में वन्यजीव गणना</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ राजस्थान में 1 और 2 मई, 2026 (वैशाख पूर्णिमा) को वॉटर होल पद्धति से वार्षिक वन्यजीव गणना सम्पन्न हुई।</li><li>■ 'वाटर होल पद्धति' (जिसे 'मचान गणना' भी कहा जाता है) वन्यजीवों की संख्या का आकलन करने का एक पारंपरिक और प्रभावी तरीका है।</li><li>■ <b>आयोजन अवधि</b> : 1 मई शाम 5 बजे से 2 मई, 2026 को शाम 5 बजे तक।</li></ul>

UTKARSH

CIVIL SERVICES

## राष्ट्रीय परिदृश्य

### ISSF जूनियर विश्व कप, 2026

#### चर्चा में क्यों?

- भारतीय निशानेबाजों ने काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप, 2026 में 16 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया।

AIR PISTOL



GOLD MEDAL

Picture Courtesy : ISSF



10m Air Pistol Mixed Team Junior

Vanshika CHAUDHARY  
Chirag SHARMA

ISSF JUNIOR WORLD CUP  
RIFLE / PISTOL / SHOTGUN  
CAIRO, EGY  
19 - 27 APR 2026

thenrai.in

--:9:--

# Daily Current Affairs

Date : 04 May, 2026



## मुख्य बिन्दु:

- **आयोजन:** 19 से 27 अप्रैल, 2026 तक मिस्र के काहिरा में आयोजित की गई, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाएँ शामिल थी।
- **भागीदारी:** काहिरा शूटिंग मीट में 25 महासंघों के 284 निशानेबाजों ने भाग लिया। भारत ने 71 एथलीटों के साथ सबसे बड़ा दल भेजा।

## रैंकिंग:

रैंक	देश/ अन्य	पदक
1 <sup>st</sup>	भारत	16 पदक: इन पदकों में 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं।
2 <sup>nd</sup>	तटस्थ एथलीट	12 पदक: इन पदकों में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं।
3 <sup>rd</sup>	फ्रांस	6 पदक: इन पदकों में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं।

## भारत के प्रमुख खिलाड़ी:

- **हेमंत बर्मन:** हेमंत बर्मन ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि कजाकिस्तान के ओलेग नोस्कोव ने जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता।
- **वंशिका चौधरी और चिराग शर्मा:** 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में वंशिका चौधरी और चिराग शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं, मोहिनी सिंह और हिमांशु राणा ने कांस्य पदक जीता।
- **प्राची गायकवाड़:** प्राची गायकवाड़ ने जूनियर महिला 50 मीटर राइफल स्पर्धा के फाइनल में 354.6 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने डार्या चुप्रिस को बेहद करीबी मुकाबले में हराया।

--:10:--

# Daily Current Affairs

Date : 04 May, 2026



- **नारेन प्रणव:** नारेन प्रणव ने जूनियर पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में 229.5 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।
- **शिव नरवाल:** शिव नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है।
- **मिश्रित ट्रैप टीम स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक:** मिश्रित ट्रैप टीम स्पर्धा में, जुहैर खान और अद्या कात्याल ने कांस्य पदक जीता। हंगरी ने जूनियर विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता।
- **कन्यान रोहित:** 50 मीटर राइफल लेटकर अभ्यास (पुरुष जूनियर) में रजत पदक जीता।
- **पिछले वर्ष का रिकॉर्ड:** सुहल और नई दिल्ली में पिछले साल के ISSF जूनियर विश्व कप चरण में, भारत ने 17 स्वर्ण सहित 37 पदक जीते थे।

UTKARSH

CIVIL SERVICES

-:11:-

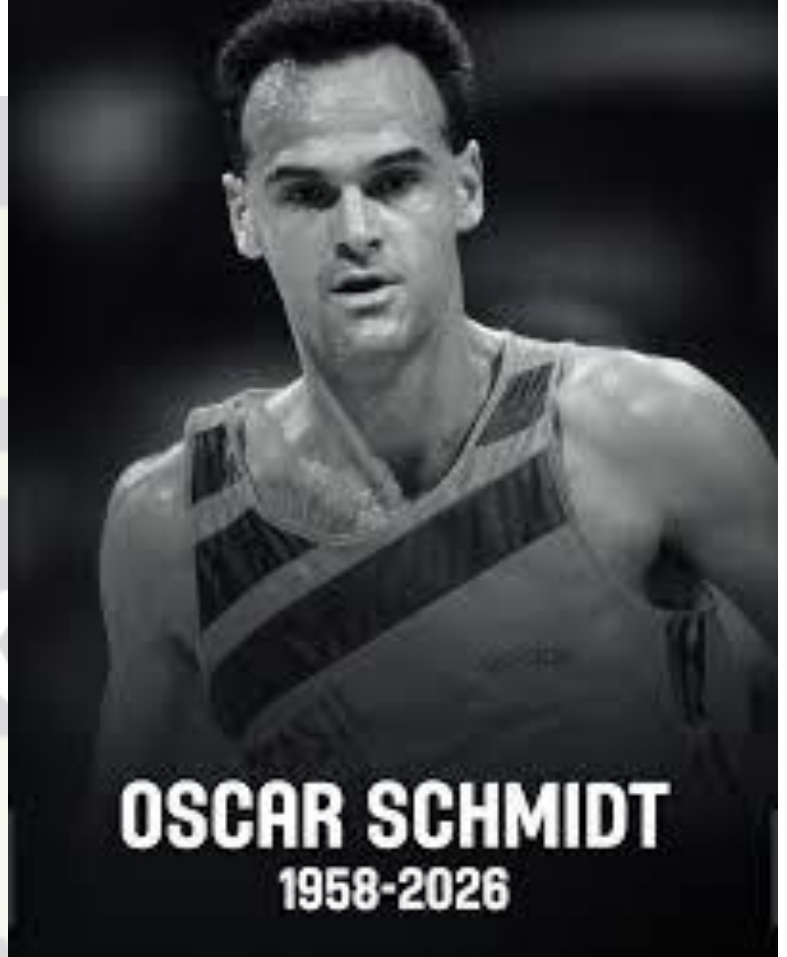
## ऑस्कर श्मिट

### चर्चा में क्यों?

- बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे अधिक स्कोर करने वालों खिलाड़ियों में से एक ब्राजील के ऑस्कर श्मिट का देहांत हो गया है।

### मुख्य बिन्दु:

- ब्राजील और यूरोप में 30 साल के पेशेवर करियर के बाद श्मिट ने वर्ष 2003 में संन्यास ले लिया था। वर्ष 2013 में उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था।
- श्मिट ने पाँच ओलंपिक खेलों और चार विश्व कप में ब्राजील का प्रतिनिधित्व किया और दोनों प्रतियोगिताओं में सर्वकालिक स्कोरिंग रिकॉर्ड अपने नाम किया।
- क्लब और देश के लिए श्मिट का 49 हजार 737 अंकों का अनौपचारिक विश्व रिकॉर्ड वर्ष 2024 में लेब्रॉन जेम्स ने तोड़ा।



## 15 वाँ यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड, 2026

### चर्चा में क्यों?

- भारत ने फ्रांस के बोर्डो में आयोजित 15वें यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड, 2026 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की हैं।



### मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड (IGMO) हाई स्कूल के छात्रों के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिताओं में से एक है, और यह विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित सबसे बड़ी प्रतियोगिता है।
- **आयोजन:** 9 से 15 अप्रैल, 2026 तक फ्रांस के बोर्डो में आयोजित किया गया।

# Daily Current Affairs

Date : 04 May, 2026



- **भागीदार:** IGMO के वर्ष 2026 संस्करण में 67 देशों के 260 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें 41 यूरोपीय देशों के 161 प्रतिभागी शामिल थे।

## भारत की स्थिति:

- भारतीय टीम का नेतृत्व डॉ. वैदेही थाट्टे (नेतृत्वकर्ता), डॉ. मृदुल थाट्टे (उपनेतृत्वकर्ता) और अदिति मुथखोद (प्रतियोगियों के साथ पर्यवेक्षक) ने किया।
- **स्वर्ण पदक:** मुंबई की श्रेया शांतनु मुंधादा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वे चार सदस्यीय भारतीय टीम का हिस्सा थीं।
- **रजत पदक व कांस्य पदक:** केरल की संजना फिलो चाको ने रजत पदक और तमिलनाडु की शिवानी भरत कुमार ने कांस्य पदक जीता।
- **भारत का प्रदर्शन:** भारत ने 67 प्रतिभागी देशों में छठा स्थान हासिल करके अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
- भारत वर्ष 2015 से अतिथि राष्ट्र के रूप में ओलंपियाड में भाग ले रहा है।

--:14:--



## भूगोल एवं भू-विज्ञान



### सुपर एल नीनो



#### चर्चा में क्यों?

- वैज्ञानिकों ने 2026 के अंत में "सुपर" एल नीनो की संभावना का पूर्वानुमान लगाया है। इसने तीव्र लू, हीटवेव, सूखे, बाढ़ और चरम मौसमी घटनाओं को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।



#### मुख्य बिन्दु:

#### सुपर एल नीनो

- यह असाधारण रूप से गंभीर एल नीनो घटना है। इसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री जल सतह का तापमान लगातार सामान्य से 2°C से अधिक बढ़ जाता है।
- एल नीनो, एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) का उष्मीय चरण है। इसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जो प्रायः भारतीय मानसून को कमजोर कर देता है।

-:15:-

## आर्थिक घटनाक्रम

### राज्यों की वित्तीय स्थिति

#### चर्चा में क्यों?

- वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में चेतावनी दी है कि उच्च राजस्व घाटे और भारी ऋण बोझ वाले कई भारतीय राज्यों को राजकोषीय झटकों से निपटने में कठिनाई होगी।



#### मुख्य बिन्दु:

- **राजस्व घाटा** : यह तब होता है, जब किसी सरकार का नियमित व्यय (जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान) करों और शुल्कों से होने वाली उसकी नियमित आय से अधिक होता है।

- **राजस्व अधिशेष:** इसका तात्पर्य यह है कि राज्य अपने राजस्व व्यय (वेतन, पेंशन, सब्सिडी) को अपनी स्वयं की प्राप्तियों से पूरा करने में सक्षम हैं, जिससे दैनिक खर्चों के लिए उधार पर निर्भरता कम हो जाती है, और इस प्रकार राजकोषीय स्थिरता में सुधार होता है।

## राजकोषीय तनाव

- यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है, जहां सरकारी राजस्व और व्यय के बीच असंतुलन होता है, जिससे नीति निर्माताओं को खर्च को समायोजित करने, राजस्व बढ़ाने या उधार बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

## वित्तीय तनाव के कारण

- **संरचनात्मक कारक:** सीमित कर आधार, जीएसटी संग्रह में असमानता और अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता।
- खाद्य पदार्थों, उर्वरकों और ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं में वृद्धि।
- **ऋण का बोझ :** उच्च उधार और ब्याज भुगतान विकास व्यय को बाधित करते हैं।
- **आर्थिक झटके:** महामारी से संबंधित व्यय, वैश्विक वस्तु कीमतों में अस्थिरता और जलवायु संबंधी आपदाएँ।
- **अनुपालन संबंधी कमियाँ:** कर चोरी, कमजोर प्रवर्तन और पूँजीगत व्यय में अपर्याप्त प्रदर्शन।

## प्रभाव

- **बढ़ता कर्ज का बोझ:** राजकोषीय तनाव से कर्ज बढ़ता है, ब्याज का बोझ बढ़ता है और विकास पर होने वाला खर्च कम होता है, जिससे क्रेडिट रेटिंग में गिरावट का खतरा बढ़ जाता है।
- **राजकोषीय संसाधनों में कमी:** राजकोषीय दबाव से सरकार की लचीलता कम हो जाती है और बुनियादी ढाँचे और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश सीमित हो जाता है।

- **व्यापक आर्थिक अस्थिरता:** सरकार द्वारा भारी मात्रा में उधार लेने से ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, जिससे निजी क्षेत्र के निवेश पर प्रतिबंध लग जाता है।
- **कमजोर सामाजिक और विकासात्मक परिणाम :** राजकोषीय दबाव स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण पर होने वाले खर्च को सीमित कर सकता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में असमानता बढ़ने की संभावना है।
- **अंतर-पीढ़ीगत बोझ :** अधिक उधार लेने से ऋण चुकाने का भार भावी पीढ़ियों पर आ जाता है, जिससे दीर्घकालिक ऋण स्थिरता जोखिम बढ़ जाते हैं, खासकर यदि विकास धीमा हो जाता है।

## राज्यों की राजकोषीय स्थिति से संबंधित आँकड़े

### राजस्व अधिशेष बनाम घाटे वाले राज्य

- **राजस्व अधिशेष वाले राज्य:** झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना
- अपनी आय से नियमित खर्चों (वेतन, पेंशन, सब्सिडी) का वित्तपोषण करने में सक्षम।
- भारत के आठ राज्यों - गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार और गोवा ने अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% या उससे कम पर बनाए रखा है।
- यह वित्तीय अनुशासन के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मानदंड के अनुरूप है।
- अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग (2026-31) ने भी राज्यों के लिए 3% राजकोषीय घाटे की सीमा की सिफारिश की है।
- **राजस्व घाटे वाले राज्य :** पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश
- पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे उच्च निश्चित खर्चों के कारण संघर्ष।
- **राज्यों में ऋण स्तर:** पंजाब सबसे अधिक ऋणी है (जीएसडीपी का 45.1%), उसके बाद हिमाचल प्रदेश (40.5%), राजस्थान और आंध्र प्रदेश (36%) का स्थान आता है।
- ओडिशा और गुजरात पर अपेक्षाकृत कम कर्ज है, जो उनकी मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत देता है।

## भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

### ई-कोर्ट मिशन

#### चर्चा में क्यों?

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सिक्किम को देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया।



#### मुख्य बिन्दु:

- पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सभी न्यायिक प्रक्रियाएँ कागज के बजाय डिजिटल माध्यम से की जाती हैं, जैसे—डिजिटल फाइलें, ई-फाइलिंग, ऑनलाइन सुनवाई, डिजिटल केस ट्रैकिंग आदि।
- न्यायालयों का यह डिजिटल रूपांतरण 'ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट' के तहत किया जा रहा है।

#### 'ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट'

- यह प्रभावी और सुलभ न्याय सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए न्यायपालिका को कम्प्यूटरीकृत और डिजिटल बनाने की एक अखिल भारतीय पहल है।
- **शुरुआत:** इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत 2007 में शुरू किया गया।
- **कार्यान्वयन प्राधिकरण:** इसका कार्यान्वयन भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के मार्गदर्शन में भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा किया जाता है।



## अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



### USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट



#### चर्चा में क्यों?

- भारत को 'स्पेशल 301 रिपोर्ट' की 'प्राथमिकता निगरानी सूची' में बरकरार रखा गया है। इसका अर्थ है कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा और उसके अनुपालन को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।



#### मुख्य बिन्दु:

#### स्पेशल 301 रिपोर्ट

- **जारीकर्ता:** इसे व्यापार अधिनियम, 1974 के तहत, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) द्वारा।
- यह रिपोर्ट उन देशों को चिह्नित करती है, जो USTR के अनुसार बौद्धिक संपदा अधिकार की पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा नहीं देते या अमेरिका के IPR धारकों को न्यायसंगत और समान बाजार पहुँच उपलब्ध नहीं कराते।
- यह रिपोर्ट कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन व्यापार वार्ता में दबाव बनाने के साधन के रूप में उपयोग की जाती है।

## पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

### भारत में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण संकट

#### चर्चा में क्यों?

- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (CSIR-NEERI) के एक हालिया अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि भारत के दशकों पुराने कचरे के ढेर माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रहे हैं।



#### मुख्य बिन्दु:

- माइक्रोप्लास्टिक:** ये छोटे सिंथेटिक प्लास्टिक कण होते हैं। इनका आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है। ये बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं या औद्योगिक उपयोग के लिए सीधे उत्पादित किए जाते हैं।

--:21:--

## प्रकार:

- **प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक:** ये छोटे आकार में कृत्रिम रूप से बनाए गए प्लास्टिक होते हैं (जैसे माइक्रोबीड्स, औद्योगिक पेलेट्स)।
- **द्वितीयक:** ये बड़े प्लास्टिक अपशिष्ट के टूटने से बनते हैं। ये सूर्य की रोशनी, गर्मी और घर्षण के कारण धीरे-धीरे छोटे कणों में बदल जाते हैं।

## CSIR अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- **प्रसार:** लैंडफिल से निकलने वाला रिसाव और मौसमी पवनें माइक्रोप्लास्टिक को भूजल, कृषि भूमि (मृदा), शहरी क्षेत्रों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुँचा देती हैं।
- ये छोटे लेकिन विषाक्त कण स्थानीय कृषि, पेयजल, खाद्य श्रृंखला और मानव स्वास्थ्य के लिए प्रत्यक्ष जोखिम उत्पन्न करते हैं।
- **मुख्य उत्तरदायी कारक:** पॉलीएथिलीन और पॉलिप्रोपिलीन सबसे अधिक प्राप्त होने वाले प्लास्टिक हैं। ये मृदा को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे खाद्य उत्पादन प्रभावित होता है।
- **नीतियों में कमियाँ:** स्वच्छ भारत मिशन जैसी वर्तमान पहलों में लैंडफिल के प्रबंधन के दौरान माइक्रोप्लास्टिक के उत्सर्जन पर निगरानी के लिए विशेष तंत्र की कमी है।
- **शासन के स्तर पर कमी:** भारत के लिए मानकीकृत निगरानी ढाँचे की कमी के कारण प्रभावी विनियमन और साक्ष्य-आधारित अपशिष्ट प्रबंधन में बाधा उत्पन्न होती है।

## भारत में पुराने लैंडफिल से निपटने के लिए पहलें

- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM-U 2.0):** इसके तहत वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन और पुराने लैंडफिल के उपचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत पुराने डंपसाइट्स की पहचान की गई है और 61% से अधिक पुराने अपशिष्ट स्थलों का निपटान किया जा चुका है।

--:22:--

# Daily Current Affairs

Date : 04 May, 2026



- **अपशिष्ट प्रबंधन नियम:** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016/2026), प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016), और ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2022) अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) तंत्र को बढ़ावा देते हैं।
- **गोवर्धन योजना:** यह योजना लैंडफिल के बोझ को कम करने के लिए बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को बायोगैस और जैविक खाद में रूपांतरण को बढ़ावा देती है।
- **लिगेसी वेस्ट बायोमाइनिंग:** नगर निकाय बायोमाइनिंग और बायो-रिमेडिएशन के माध्यम से पुराने डंपसाइट्स को पुनः उपयोगी बना रहे हैं।
- **सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध (2022):** इसके तहत प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ चिह्नित सिंगल-यूज प्लास्टिक प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

## ⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी 🌡️

### प्रोजेक्ट 17A पोत

#### 📢 चर्चा में क्यों?

- INS महेंद्रगिरि को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। यह नीलगिरि-श्रेणी (प्रोजेक्ट 17A) का छठा और मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित चौथा पोत है।



#### 📌 मुख्य बिन्दु:

- प्रोजेक्ट 17A के अन्य पोत हैं: दूनागिरि, तारागिरि, उदयगिरि, हिमगिरि, नीलगिरि।
- प्रोजेक्ट 17A के तहत आधुनिक फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं। ये बहुउद्देशीय और कई मिशनों वाले युद्धपोत हैं।
- इन्हें वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और वॉरशिप ओवरसीइंग टीम (मुंबई) द्वारा इसकी निगरानी की गई है।
- P17A जहाजों को P17 (शिवालिक-श्रेणी) की तुलना में उन्नत हथियारों और सेंसर सूट से सुसज्जित किया गया है।
- ये तीन तरह के युद्ध में सक्षम हैं: सतह पर हमला, हवा में हमला, पनडुब्बी के खिलाफ।
- ये पोत कंबाइंड डीजल या गैस प्रणोदन संयंत्रों से सुसज्जित हैं। इनमें एक डीजल इंजन और एक गैस टर्बाइन, शामिल होते हैं।

--:24:--